आकाशवाणी केन्द्र शिमला
08.11.2025/प्रादेशिक समाचार/1800 बजे

संसद सत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पहली दिसंबर से 19 दिसम्बर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूत करने सहित देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे।

जगत सिंह नेगी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार एच.पी.एम.सी. के उत्पादों को देश में अधिक लोकप्रिय बनाने और इनकी बिक्री बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रही है। सोलन ज़िले के परवाणू में आज एच.पी.एम.सी. संयंत्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और इनमें विविधता लाने के लिए कार्यरत है। बागवानी मंत्री ने बताया कि किसानों व बागवानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और बेहतर विपणन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठ के सहारे चल रही प्रदेश सरकार से हर वर्ग निराश है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई हिम केयर जैसी योजना को बंद कर दिया है जिसके चलते लोग इलाज के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं या फिर इलाज ही नहीं करवा पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने पिछले 3 वर्षों में करीब डेढ़ हज़ार से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं जिससे स्थानीय बच्चों को भारी असुविधा हुई है। मीडिया में आई एक खबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में एक सौ 16 बच्चे ठण्ड के इस मौसम में भी तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाने का दावा कर रही है लेकिन हकीकत इससे विपरीत है।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल–कोटखाई क्षेत्र के टिक्कर में आज करीब 7 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली कडीवन, उमलाडवार, गालून सड़क का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जुब्बल–कोटखाई क्षेत्र में करीब 5 सौ करोड़ रूपए के सड़क निर्माण व मुरम्मत कार्य प्रगति पर हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में क्षेत्र के लिए एक सौ 10 करोड़ रूपए स्वीकृत हुए हैं।

जीएसटी

अगली पीढ़ी के जी.एस.टी. सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमी की पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंट पर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस

फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकान खरीददारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट.....

अगलीपीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमीकी पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंटपर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकानखरीदारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकोंपर अब 12 प्रतिशत की जगह केवल 5 प्रतिशतजीएसटी लगेगा, जिससे फर्श और फिनिशिंग की लागत कम हो जाएगी। इसीप्रकार, रेत–चूने की ईंटों पर भी कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है,जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके साथ ही ईंटों के जॉब वर्कपर जीएसटी को भी 12 प्रतिशत के कर स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आवास की लागत कम हुई है और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग– एमएसएमई को समर्थन मिला है। संशोधित ढांचे के तहत यह युक्तिकरण न केवल निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को मजबूत कर रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है, बल्किघरों और बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती भी बना रहा है।

धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करना राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 10 नवम्बर को मण्डी में एक कार्यक्रम में आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के परिवारजनों को चार–चार लाख रूपए की राहत राशि वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद प्रभावितों की राहत राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

हमीरपुर भाजपा

हमीरपुर ज़िला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की परिचय बैठक आज हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में मोर्चा अध्यक्ष राज कुमार ने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान हमीरपुर ज़िला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकारों ने प्रदेश में सड़क विकास को व्यापक प्रोत्साहन दिया जिससे दूरदराज़ और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ।